RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 05 FEBRUARY TO 11 FEBRUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 24 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कोरोना वायरस असर, वाहन प्रदर्शनी, पर्यटन क्षेत्र कुछ उद्योगों पर दिखा असर
Page 3

अगले 3 साल में भारत को मिल जाएंगे सैन्य कमान
Page 4

Maruti Suzuki Futuro-e कॉन्सेप्ट कार से उठा पर्दा
Page 7

editoria!

उम्मीद की किरण

आर्थिक क्षेत्र में निराशा का दौर इस बार कुछ ज्यादा लंबा हो गया है। यह पूरी तरह खत्म हो गया है, इसे कहने का वक्त शायद अभी नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरणें दिखने लग गई हैं। जनवरी महीने में मैन्युफैक्चरिंग का हाल बता रहे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने जो बढ़त दिखाई है, वह इसलिए बहुत सकारात्मक है कि यह इंडेक्स इस समय पिछले आठ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने में यह इंडेक्स 52.7 पर था, जो जनवरी में बढ़कर 55.3 पर पहुंच गया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो गणित है, उसके हिसाब से अगर यह 50 से नीचे होता है, तो इसका अर्थ है कि चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं, इससे ऊपर है, तो इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था विस्तार की ओर है। यह सूचकांक हमें सिर्फ उत्पादन के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि मांग, बिक्री, कच्चे माल की खपत, उत्पादन और रोजगार के बारे में भी काफी कुछ कहता है। यानी इस सूचकांक के बढ़ने का अर्थ सिर्फ फैक्टरियों में होने वाले उत्पादन का बढ़ना भर नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हरेक गतिविधि में तेजी आना है। लंदन की कारोबारी सूचना कंपनी आईएचएस मार्केट विभिन्न देशों के लिए इस सूचकांक को जारी करती है। इस सूचकांक के हिसाब से भारत की इस समय जो स्थिति है, उसे बहुत आदर्श भले ही न कहा सकता हो, लेकिन उसमें सकारात्मक दिशा की ओर संकेत जरूर दिख रहे हैं। यह सूचकांक 2020-21 के बजट के ठीक बाद आया है। इस बजट से काफी लंबे समय से यह उम्मीद बांधी जा रही थी कि इससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकेगी। हालांकि बजट बाद की प्रतिक्रियाएं यह भी बता रही हैं कि उसके प्रावधानों से हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोगों की उम्मीदों पर भले ही यह बजट खरा उतरा हो, लेकिन इससे बाजार को कोई नई गति मिलेगी, यह फिलहाल नहीं कहा जा रहा। ऐसी स्थिति में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने यह संकेत दिए हैं कि भारतीय बाजार को नई गति मिलनी शुरू हो गई है। वह भी बजट से काफी पहले ही। जाहिर है, बजट को अब इस तरह देखना होगा कि वह इस गति में कुछ जोड़ रहा है या नहीं। बजट की भूमिका को अगर छोड़ भी दें, तब भी लंबी चली सुस्ती के बाद तरक्की की इस रफ्तार को लौटना ही था। जिस समाज के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हो और पूरी तरह विकसित बाजार हो, उसकी गति अपने आप ही देर-सवेर पटरी पर आएगी, इसमें कभी कोई शुबहा नहीं रहा है। पिछले कुछ समय से जो निराशाएं दिख रही थीं, उनका कारण यह था कि इस बार इसने पटरी पर आने में काफी देर कर दी। और अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिख रही है, तब मूल मुद्दा यह है कि इसकी रफ्तार को कैसे तेज किया जाए। यह माना जाता है कि जनसंख्या अनुपात में युवाओं की आबादी का अधिक होना बहुत लंबे समय तक हमारा सच नहीं रहेगा। इसके पहले कि भारत इस अनुपात से दूर होने लगे, इतने तेज विकास की जरूरत है कि जल्द से जल्द ज्यादातर नौजवानों को काम और ज्यादातर परिवारों को समृद्धि दी जा सके। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, तो देश बिना समृद्धि के स्तर को छुए बूढ़ा होने की ओर बढ़ चलेगा। फिलहाल जिस बढ़त की झलक मिली है, उसे बहुत आगे ले जाना होगा।

सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां नए वित्त वर्ष में करेंगी 98,521 करोड़ रुपए का निवेश

नयी दिल्ली। एजेंसी

ओएनजीसी, इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां तेल एवं गैस खोज, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन और पाइपलाइन बिछाने पर यह निवेश करेंगी ताकि दुनिया ऊर्जा खपत के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ते देश की जरूरत को पूरा किया जा सके। बजट दस्तावेजों के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब चार प्रतिशत अधिक निवेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में उनका निवेश 94,974 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

आयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का अगले वित्त वर्ष में निवेश 19 प्रतिशत बढ़कर 32,501 करोड़ रुपये रहेगा। ओएनजीसी की विदेश इकाई ओएनजीसी विदेश लि. ओवीएल देश के बाहर तेल एवं गैस परिचालन पर 7,235 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) का निवेश 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 26,233 करोड़ रुपये रहेगा।

निजीकरण की ओर अग्रसर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) ने अगले वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है। गैस कंपनी गेल इंडिया लि. का निवेश 5,412 करोड़ रुपये रहेगा। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। ओएनजीसी की अनुषंगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी आयल इंडिया लि. (ओआईएल) अगले वित्त वर्ष में 3,877 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। चालू वित्त वर्ष में उसका निवेश 3,675 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

कच्चा तेल फिसला $ 50 के नीचे

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल के दाम पर अभी भी वायरस का डर मंडराए जा रहा है और इसी कारण WTI क्रूड के दाम $ 50 /बैरल के नीचे लुढ़क गए हैं, उसी के साथ ब्रेंट के दाम भी $ 54 / बैरल के नीचे फिसल गए। वायरस अभी भी बढ़ता जा रहा है और छीने में 490 लोगो की मौत हो गयी और 24 ,000 लोग इसकी चपेट में आ गए। एक समय पर $ 70/ बैरल के करीब जाने के बाद ब्रेंट और WTI क्रूड के दाम लगातार गिरते जा रहा हैं क्यूंकि ऐसा माना जा रहा है की वायरस के कारण कच्चे तेल की डिमांड कम हो सकती है और इसी वजह से दाम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालाँकि OPEC ने कहा है की वो उत्पादन में और कटौती करेगा लेकिन उसके बाजवूद भी दाम फिसलते ही जा रहे हैं।

रणनीतिक भंडारगृहों की कच्चे तेल की बिक्री आय को बजट में दी गई कर छूट

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेशी कंपनियों को भारत के रणनीतिक तेल भंडार में रखे गये तेल की बिक्री पर कर छूट देने के बाद आम बजट 2020-21 में भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भी रखे गये कच्चे तेल की खरीद- बिक्री से होने वाली आय पर कर छूट दी गई है। सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों में रखे गये कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय पर 2017 में कर छूट दे दी थी।बजट दस्तावेज के अनुसार, आईएसपीआरएल को देश के रणनीतिक भंडारगृहों में रखे गये कच्चा तेल की बिक्री पर आयकर से छूट दी गयी है। हालांकि, इसके साथ ही यह शर्त है कि कंपनी को तीन साल के भीतर भंडार में वापस उतना ही कच्चा तेल भरना होगा।कंपनी के लिये नयी व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017- 18 के बजट में रणनीतिक तेल भंडार में भंडारण क्षमता की बुकिंग करने वाली कंपनियों के आय को कर से छूट दे दी थी।

Crude Oil की कीमत में गिरावट थमने से पेट्रोल-डीजल पर भी पड़ा असर, ठहर गए दाम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी गिरावट का सिलसिला थम गया है। पिछले दो दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी दिखने के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उससे पहले लगातार गिरावट के चलते क्रूड ऑयल का भाव 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से लुढ़ककर 50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ गया था। क्रूड ऑयल की कीमतों में यह तेज गिरावट जानलेवा कोरोना वायरस के चलते देखने को मिल रही है। इस दौरान पेट्रोल व डीजल के दाम में भी करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक की गिरावट आयी। आइए जानते हैं कि आज पेट्रोल डीजल व क्रूड ऑयल क्या भाव बिक रहा है। क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई का फ्यूचर भाव बुधवार सुबह 1.07 फीसद की बढ़त के साथ 50.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 1.20 फीसद की बढ़त के साथ 54.61 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट थमने से देश के बड़े महानगरों में बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल अपने पुराने भाव 72.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 66.04 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

कोलकाता में आज पेट्रोल 75.65 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 68.41 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में आज पेट्रोल 78.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 69.22 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में आज पेट्रोल 75.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 69.76 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। जयपुर की बात करें, तो यहां बुधवार को पेट्रोल 76.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.06 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल बुधवार को 74.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 66.30 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं, गुरुग्राम में पेट्रोल 72.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल 65.31 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।

Coronavirus के चलते एक साल के न्यूनतम स्तर पर आए कच्चे तेल के दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। चीन और उसके पड़ोसी देशों में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते तेल की कीमतों में यह गिरावट देखी गई है। कोरोना वायरस से तेल की वैश्विक मांग में कमी आई है। इस वायरस के चलते अकेले चीन की तेल खपत में 20 फीसद तक की गिरावट आ गई है। मांग में कमी के चलते कच्चे तेल की फ्यूचर प्राइस मंगलवार को 50 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गई, जो कि करीब एक साल का न्यूनतम स्तर है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा असर

की कीमत में बीती 12 जनवरी से करीब तीन रुपये प्रति लीटर तक की गिरावट आ चुकी है। क्रूड ऑयल WTI का फ्यूचर भाव मंगलवार सुबह साढ़े चार बजे करीब 49.78 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था, जो कि करीब एक साल का इसका न्यूनतम स्तर है। क्रूड ऑयल का फ्यूचर भाव आज मंगलवार को 49.92 बैरल प्रति लीटर पर खुला है और सुबह 9 बजे तक इसके भाव ने 49.66 डॉलर प्रति लीटर से 50.59 डॉलर प्रति लीटर के बीच ट्रेंड किया है। गौरतलब है कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर प्राइस पिछले सत्र में 50.11 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था।

वहीं, ब्रेंट ऑयल की बात करें, तो यह मंगलवार सुबह सवा तीन बजे 54.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा था। ब्रेंट ऑयल मंगलवार को 54.18 डॉलर प्रति औंस पर खुला है और सुबह 9 बजे तक इसके फ्यूचर भाव ने 53.95 डॉलर प्रति बैरल से 54.86 डॉलर प्रति बैरल के बीच में ट्रेंड किया है। गौरतलब है कि ब्रेंट ऑयल का फ्यूचर भाव पिछले सत्र में 54.45 डॉलर प्रति बैरल बर बंद हुआ था। चीन की एनर्जी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े आयातक की तेल डिमांड में करीब तीन मिलियन बैरल प्रति दिन की गिरावट आई है। मांग में यह गिरावट कोरोना वायरस के चलते काम-काज रुक जाने के कारण आई है।

घरेलू मांग बढ़ने से जनवरी में सात साल के उच्चतम स्तर पर आई देश की Services PMI

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय सर्विस सेक्टर के लिए साल 2020 की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है। घरेलू मांग के मजबूत होने से जनवरी 2020 में सर्विस पीएमआई (Services PMI) सात साल के उच्चतम स्तर पर आ गई है। आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स में जनवरी 2020 में बढ़ोत्तरी हुई है। यह जनवरी में 55.5 हो गई है, जो कि पिछले साल दिसंबर में 53.3 थी। एक प्राइवेट सर्वे से बुधवार को यह आंकड़ा पता लगा है।

सर्विस इंडस्ट्री भारत की बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। इस सेक्टर की एक्टिविटी में वृद्धि होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। मजबूत घरेलू मांग के चलते इस सेक्टर की एक्टिविटी की रफ्तार सात सालों में सबसे तेज दर्ज की गई है। सर्विस पीएमआई में तेजी बाजार और पॉलिसीमेकर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। जनवरी 2020 में दर्ज की गई सर्विस पीएमआई जनवरी 2013 के बाद की सबसे अधिक सर्विस पीएमआई है।

आईएचएस मार्किट (IHS Markit) की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट Pollyanna De Lima ने एक रिलीज में कहा, 'भारतीय सर्विस सेक्टर ने साल 2020 की शुरुआत में तेजी की दिशा में अच्छी उछाल प्राप्त की है। इसने सुस्ती को नकार कर साल 2019 के आखिर में हासिल की गई बढ़त को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है।'

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

बिजनेस रेवेन्यू के बढ़ने के साथ ही सर्विस प्रोवाइडर्स बिक्री में आगे मजबूत ग्रोथ को हासिल करने के लिए अपनी क्षमता में बढ़ोत्तरी करेंगे। सर्विस पीएमआई का बढ़ना नौकरियां ढूंढ़ रहे लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है।नए कारोबारों को ट्रैक करने वाला एक सब इंडेक्स भी जनवरी 2013 के बाद के उच्चतम स्तर पर आ गया है। इससे कंपनियों को हायरिंग दर को मजबूत बनाए रखने का प्रोत्साहन मिलेगा।

वहीं, सोमवार को एक सिस्टर सर्वे से पता चला है कि देश की फैक्ट्री एक्टिविटी ने पिछले महीने आठ सालों की सबसे तेज रफ्तार प्राप्त की है। यह जनवरी 2013 के बाद से सबसे ज्यादा 56.3 फीसद हो गई है।

कोरोना वायरस असर

वाहन प्रदर्शनी, पर्यटन क्षेत्र कुछ उद्योगों पर दिखा असर

नयी दिल्ली। एजेंसी

खतरनाक कोरोना वायरस का देश में हो रही वाहन प्रदर्शनी पर असर पड़ रहा है। वहीं पर्यटन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समेत कुछ अन्य क्षेत्र अपने कारोबार पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिये स्थिति पर नजर रखे हुए है। वाहन कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने कहा कि प्रदर्शनी में भाग ले रही सभी चीनी कंपनियों ने कहा है कि प्रदर्शनी में उनके मंडप पर भारतीय कर्मचारी ही होंगे। वाहनों के कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों के संगठन ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एकमा) ने भी कहा कि चीन से करीब 30 कंपनियो ने प्रगति मैदान में उपकरण प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने की पुष्टि की है। उनकी अनुपस्थिति में उसका प्रबंधन भारतीय कर्मचारी करेंगे।

वाहन प्रदर्शनी-2020-उपकरण प्रदर्शनी प्रगति मैदान में 6 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान हो रही है। जबकि आटो एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित प्रदर्शनी स्थल में किया जा रहा है। इस बीच, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा कि चीन और भारत के बीच यात्रा पाबंदी से बुकिंग पर असर पड़ रहा है और पर्यटन उद्योग स्थिति पर नजर रखे हुए

है।उल्लेखनीय है कि भारत ने रविवार को चीनी यात्रियों और पड़ोसी देश में रहने वाले विदेशियों के लिये ई-वीजा सुविधा पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों ने 15 जनवरी से चीन की यात्रा की है, उन्हें पृथक वार्ड में रखा जाएगा। मेक माई ट्रिप के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश मैगो ने कहा, ''चीन और यहां तक कि हांगकांग यात्रा पर पाबंदी से यात्रा बुकिंग पर बुरा असर पड़ा है।''मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वे यह देख रहे हैं कि क्या आपूर्तिकर्ताओं के बंद कारखाने अगले सप्ताह से खुलेंगे। मोबाइल उद्योग सालाना करीब 95,000 करोड़ रुपये मूल्य का उपकरण आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है।

इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन (आईसीईए) के चेयरमैन पंकज महेन्द्रू ने कहा, ''चीन के नये साल के अवसर पर वहां बाजार बंद रहता है। इसको देखते हुए कंपनियों ने कुछ अधिक उपकरण मंगाकर रखे थे। बाजार में अभी भंडार हैं। यह 10-15 फरवरी तक रहेगा। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर समस्या 10 फरवरी के बाद भी बनी रहती है, तब समस्या होगी।''इस बीच, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी चीन में फैले कोरोना वायरस का असर जूता उद्योग पर दिखाई देने लगा है। चीन से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने से उद्योग का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ती जा रही है। जूता विनिर्माण एवं निर्यात उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने यह आशंका व्यक्त की है। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न खतरनाक विषाणु दूसरे देशों में भी फैल रहा है। इसके कारण अब तक चीन में 420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की आशंका है।

नए टैक्स स्लैब में दरें कम लेकिन ये 10 प्रमुख लाभ छोड़ने होंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

बजट में पुरानी आयकर व्यवस्था के सामानांतर एक नई कर व्यवस्था का ऐलान किया गया है। इसमें कर की दरें कम रखा गया है लेकिन बचत समेत कई तरह के मिलने वाले छूट (डिडक्शन) के लाभ को खत्म कर दिया है। बजट भाषण के मुताबिक, 70 छूट और डिडक्शन (कटौती) खत्म कर दिए गए हैं और 30 को नई कर व्यवस्था में छोड़ा गया है। आइए जानते हैं कि नई कर व्यवस्था अपनाने पर आपको किन प्रमुख लाभ को छोड़ना होगा।

1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट

अगर आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनेंगे तो अभी भी आप आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स बचत वाले निवेश विकल्पों (जीवन बीमा पीपीएफ, एफडी) में पैसे लगाते हैं तो इसके जरिये 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट हासिल कर सकेंगे। वहीं, नई कर व्यवस्था में यह लाभ नहीं मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, स्वैच्छिक प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80डी के साथ धारा 24 के हिसाब से भी आप पुरानी कर व्यवस्था से लाभ ले पाएंगे।

नई व्यवस्था में क्या बाहर

- धारा 80सी के तहत निवेश
- मकान किराया भत्ता
- यात्रा भत्ता
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
- मानक कटौती
- बचत खाता पर ब्याज
- शिक्षा ऋण का ब्याज
- राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश
- होम लाने के ब्याज पर छूट
- धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता

नई व्यवस्था में ये लाभ भी

- कृषि आय
- जीवन बीमा से आय
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से मिली रकम
- सेवा-निवृत्ति पर छुट्टी के बदले नकद भुगतान
- मृत्यु पर बीमा से मिलने वाली राशि
- जीपीएफ या पीपीएफ से मिलने वाला ब्याज
- सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि
- छात्रवृत्ति की राशि
- मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रैच्यूटी

नई कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध छूट

नई कर व्यवस्था में कृषि से होने वाली आय, अविभाजित हिंदू परिवार के किसी सदस्य को परिवार की संपत्ति से मिलने वाला धन, कंपनी के भागीदार को मिलने वाला लाभ का हिस्सा, प्रवासी भारतीयों को कुछ प्रतिभूतियों-ऋणपत्रों तथा प्रावासी खाते में रखे धन पर मिलने वाला ब्याज, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रैच्यूटी, सेवानिवृत्ति के समय बची छुट्टियों के बदले मिलने वाली नकदी वीआरएस के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि होगी कर मुक्त, जीवन बीमा पॉलिसी से बोनस समेत मिलनी वाली राशि, मृत्यु पर बीमा से मिलने वाली राशि (बिना शर्तों के), जीपीएफ या पीपीएफ आदि को शामिल किया गया है।

बैंक कर्ज में 7.21% की वृद्धि, जमा 9.51% बढ़ाः RBI

मुंबई। एजेंसी

पिछले कुछ दिनों में आए आर्थिक आंकड़े अर्थव्यवस्था में रफ्तार का संकेत दे रहे हैं। बैंक कर्ज और जमा 17 जनवरी को समाप्त पखवाड़े में क्रमशः 7.21 प्रतिशत और 9.51 प्रतिशत बढ़कर 100.05 लाख करोड़ रुपये तथा 131.26 लाख करोड़ रुपये रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार एक साल पहले इसी अवधि में बैंक कर्ज 93.32 लाख करोड़ रुपये, जबकि जमा 119.85 लाख करोड़ रुपये था। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ा आंकड़ा आया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की पीएमआई 55.3 दर्ज की गई है, जो आठ साल का ऊपरी स्तर है।

पिछले पखवाड़े में भी हुई थी बढ़ोतरी

इससे पहले, दो जनवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े में कर्ज 7.57 प्रतिशत बढ़कर 100.44 लाख करोड़ रुपये, जबकि जमा 9.77 प्रतिशत बढ़कर 132.10 लाख करोड़ रुपये था। गैर-खाद्य कर्ज दिसंबर 2019 में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इससे पहले दिसंबर 2018 में इसमें 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सेवा क्षेत्र का कर्ज 6.2% बढ़ा

सेवा क्षेत्र को कर्ज दिसंबर 2019 में 6.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आंकड़े के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कर्ज दिसंबर 2019 में 5.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी माह में इसमें 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

व्यक्तिगत कर्ज 15.9% बढ़ा

व्यक्तिगत कर्ज आलोच्य महीने में 15.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दिसंबर 2018 में इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उद्योग को दिए जाने वाले कर्ज में दिसंबर 2019 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी माह में यह 4.4 प्रतिशत थी।

सरकार देश को उच्च वृद्धि के रास्ते पर ले जाने को प्रतिबद्धः अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आम बजट को व्यवहारिक बताया और कहा कि सरकार देश को उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर ले जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार 2020-21 में विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो यह बजट की सबसे बड़ी सफलता होगी। कांत ने उद्योग मंडल फिक्की के कार्यक्रम में कहा, ''यह व्यवहारिक बजट है। इसमें कई क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को को बढ़ाया गया है। बजट में कृत्रिम मेधा (एआई), क्वांटम कंप्युटिंग, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिये पूरा खाका है। बजट भारत को सही रास्ते पर रखेगा।'' उन्होंने कहा, ''...सरकार भारत को उच्च वृद्धि के रास्ते पर ले जाने को लेकर प्रतिबद्ध है।'' हालांकि कांत ने यह भी कहा कि बजट की बड़ी चुनौती उद्योग व्यवसाय को जोश से भरने और कर्ज प्रवाह की होगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने वृहत-आर्थिक स्थिरता पर जोर दिया है। कांत ने जोर देकर कहा, ''8 से 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लिये निजी क्षेत्र में जोश जरूरी है। भारत की 3,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था केवल सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश से आगे नहीं बढ़ सकती।'' विनिवेश के बारे में उन्होंने कहा कि जहां बीपीसीएल और एयर इंडिया के विनिवेश का सवाल है, सरकार सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

बैंक जमा पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर लागू हुआ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बैंक जमा पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर मंगलवार से लागू हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश करते हुए बैंकों में जमा लोगों के धन पर गारंटी राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (ड्ढ्ढ्ढ) प्रदान करती है।

जमाकर्ताओं को संरक्षण

केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 'सेहत' की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है। इससे पहले दिन में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

पीएमसी घोटाले के मद्देनजर कदम

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी से निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी। अभी यदि कोई बैंक विफल होता है तो उस पर जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की ओर से एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। अब यह बीमा कवर बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

बजट घोषणाओं पर काम शुरू

कुमार ने ट्वीट किया, 'बजट घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने जमा बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव करीब 27 साल यानी 1993 के बाद किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि बैंक अब प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे। पहले यह 10 पैसे था। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति 2009 ने डीआईसीजीसी की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी। यह त्वरित, सुधारात्मक कार्रवाई की अधिक स्पष्ट प्रणाली है। इसके अलावा, समिति ने जमा बीमा प्रीमियम को अधिक जोखिम आधारित बनाने का भी सुझाव दिया था।

अगले 3 साल में भारत को मिल जाएंगे सैन्य कमान

सेना में होगा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अब से तीन वर्षों में भारत सैन्य इतिहास में सबसे बड़े पुनर्गठन में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के संचालन को एकीकृत करने वाले सैन्य कमानों का संचालन शुरू कर देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के बाद पहली बार अपने संबोधन में जनरल बिपिन रावत ने कहा, 'यह उनका लक्ष्?य था कि सेना के तीनों अंगों को एक ऐसे सशस्?त्र बल के रूप में विकसित करना, जिसमें उनकी क्षमताएं, साजो-सामान और सैनिक एकीकृत हों। इसका उद्देश्?य है खर्च में कमी लाना, जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना औ यह सुनिश्चित करना कि सशस्त्र बल एकजुट इकाई के रूप में लड़ें।'

कमान की संख्या को फिलहाल अंतिम रूप नहीं दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्?टाफ फिलहाल तैयार हो रहे प्रस्?तावों को देख रहे हैं, जिससे अंततः एक पश्चिमी थिएटर कमान, उत्तरी कमान जो लद्दाख से लेकर नेपाल की सीमा को कवर करेगा और जम्?मू कश्?मीर के लिए एक अलग थिएटर कमान का गठन हो सकेगा। एक पूर्वी थिएटर कमान संभवतः नेपाल के पूर्व में सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगी। इन थिएटर कमांड्स की संख्या, जो फिलहाल सेना के नेतृत्व में होगी, अभी भी तय नहीं की गई है।

पाकिस्तान और चीन से लगती जमीनी सीमाओं को कवर करने वाली इन कमांड्स के अलावा भारत के पास नेवी के तहत एक प्रायद्वीपीय कमान भी होगी। साथ ही वायुसेना के तहत एक एयर डिफेंस कमान और अंतरिक्ष कमान भी होगी। हर थिएटर कमान में एक अभिन्न वायु सेना तत्व होगा और आवश्यकता की प्रकृति के आधार पर, अतिरिक्त विमान तैनात किए जा सकते हैं। सीडीएस ने कहा, 'हमें लगता है कि वहां मौजूद सभी साजो-सामान को एक सेवा के तहत एकीकृत रहना चाहिए और नियंत्रण के मुद्दों का सरलीकरण किया जाना चाहिए।' चीफ ऑफ डिफेंस स्?टाफ और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के बीच प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तय समय के भीतर कमानों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करना उनका उद्देश्य था।

जनरल रावत ने कहा कि उच्च मूल्य वाले सैन्य अधिग्रहण, जैसे नौसेना के लिए प्रस्तावित तीसरा विमान वाहक, 'अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है, इस पर निर्भर करता है। नौसेना ने तीसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को मंजूरी देने के लिए वर्षों तक सरकार से लड़ाई लड़ी है, जो फिलहाल सेवारत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जिसका जल्द ही परीक्षण शुरू होने वाला है, का पूरक होगा।

इसी तरह, भारतीय वायुसेना के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लगता है कि उच्च सेवा सुनिश्चित करने के लिए महंगे लड़ाकू विमानों की खरीद को कम करना महत्वपूर्ण है। भारत 114 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए वैश्विक निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है।

जनरल रावत ने समझाते हुए कहा, 'मेनटेनेंस साइकल को देखें, अगर एक छोटे समय में ज्यादा विमानों का अधिग्रहण होगा तो एक साथ ही उनके रखरखाव की भी जरूरत होगी। इसका मतलब यह होगा कि इनमें से कई एक साथ एक समय के लिए कमीशन से बाहर हो जाएंगे। इसके बजाय, वायुसेना के लिए चरणबद्ध अधिग्रहण की एक प्रणाली का मतलब होगा कि कम से कम कुछ प्रमुख संसाधन जैसे कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन परिचालन के लिए उपलब्ध होंगे जबकि अन्य की सर्विस की जा रही होगी।' लागत कम करने का एक अन्य तरीका यह होगा कि बेहद उच्च गुणवत्ता वाले गोला-बारूद का देश में ही निर्माण किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर गोला-बारूद की उपयोगिता योग्य समय 10 साल है तो क्या आप उसे 20 साल के लिए स्टॉक करेंगे? यह जरूरी है कि जरूरत के वक्त तेजी से गोला-बारूद के उत्पादन करने की क्षमता विकसित की जाए।

सबसे दूरगामी प्रस्तावों में से एक, सीधे भारतीय सशस्त्र बलों के 1.33 लाख करोड़ रुपये के पेंशन बजट में कटौती करने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, जो गैर-अधिकारी रैंक के कर्मियों को 58 वर्ष की आयु तक नियोजित करने में सक्षम करेगा। जनरल रावत ने कहा, 'मुझे लगता है कि सेना के एक तिहाई लोग 58 वर्ष की उम्र तक काम कर सकते हैं। वर्तमान में सशस्त्र बलों से सैनिक 37-38 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जबकि अधिकारी सामान्यतः 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। पेंशन का बजट बहुत ज्यादा है। क्या यह टिकाऊ है?' अपनी तात्कालिक प्राथमिकताओं को बताते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि वह बर्बादी को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सप्लाइज की ओवर स्टॉकिंग को रोकेंगे और अगर संभव हुआ तो जेनरेटर और वाहनों के कलपुर्जों जैसे सामानों की जीरो स्टॉकिंग की ओर भी बढ़ेंगे क्योंकि ऐसे सामान बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिशेष यानी सरप्लस और कमियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है. संयुक्तता और अनुकूलन समय की आवश्यकता है।

GST बिल लेने वालों की खुलेगी लॉटरी

10 लाख से एक करोड़ रुपये तक की लॉटरी योजना

खरीदारी बिल लेने पर जीते सकेंगे लॉटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिए होगा

नई दिल्ली। एजेंसी

ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। इस माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की जाएगी। ग्राहक, खरीदारी जो बिल लेंगे, उसी के जरिए वे लॉटरी जीत सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा जीएसटी के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे। जोसफ ने कहा, 'हम एक नई लॉटरी प्रणाली लेकर आए हैं। जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी। इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 प्रतिशत की 'बचत' नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा। यह ग्राहक की आदत में बदलाव से जुड़ा सवाल है।'

बिल पोर्टल पर होंगे अपलोड

योजना के तहत खरीदारी के बिलों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लॉटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिए अपने आप होगा। विजेताओं को इसकी सूचना दी जाएगी। जीएसटी प्रणाली के तहत चार कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो। योजना के अनुसार लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है। जीएसटी राजस्व में कमी की वजहों को दूर करने के लिए सरकार व्यापार से उपभोक्ता सौदों में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें लॉटरी और क्यूआर संहिता आधारित लेन-देन को प्रोत्साहन देना शामिल है।

बजट 2020 में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

1 अप्रैल से शुरू होगा जीएसटी रिटर्न का आसान वर्जन

नई दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिटर्न का सरल स्वरूप अप्रैल 2020 से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि जीएसटी ने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मदद पहुंचायी है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा, ''जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद हर परिवार को मासिक व्यय में चार प्रतिशत की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नये करदाता जुड़े हैं। इसके तहत 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये हैं तथा 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए हैं। जीएसटी प्रणाली एक जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस बार जनवरी में जीएसटी के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ। यह लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि इस बार का बजट तीन चीजों पर मुख्यतौर पर केंद्रित हैं। ये तीन चीजें हैं- आकांक्षी भारत

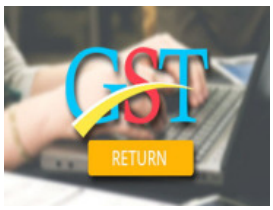

(aspirational India), सभी के लिए आर्थिक विकास (economic development) करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज (caring society)। बजट में इन तीन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बैंकों का बही खाता साफ सुथरा हुआ है। वित्त मंत्री ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा मकसद लोगों की आय और खरीद क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि 2014-19 के दौरान सरकार ने कामकाज के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने माल एवं सेवा कर को ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार करार देते हुए कहा कि इससे देश आर्थिक रूप में एकीकृत हुआ है।

बजट में आर्थिक ग्रोथ का अनुमान महत्वकांक्षीः मूडीज

नई दिल्ली। एजेंसी

मूडीज इंवेस्टर सर्विस ने कहा कि भारत की इकॉनमी के सामने संरचनात्मक और चक्रीय चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2020-21 के बजट में आर्थिक ग्रोथ का अनुमान महत्वकांक्षी लगता है। बजट में वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 12.6 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है, 'भारतीय इकॉनमी के सामने संरचनात्मक और चक्रीय चुनौतियों को देखते हुए ये अनुमान महत्वकांक्षी लगता है।' वर्ष 2019 में आर्थिक वृद्धि में यह नरमी रही। इससे पहले, बाजार आधारित वृद्धि दर 2014 से 2018 के दौरान करीब 11 प्रतिशत रही। इसमें कहा गया है,'हम उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और वर्तमान मूल्य पर आधारित जीडीपी वृद्धि 2020 में करीब 8.7 प्रतिशत और 2021 में 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2019 में यह 7.5 प्रतिशत थी।

अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर

मांग बढ़ने से जनवरी में 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग ऐक्टिविटी

बेंगलुरु। एजेंसी

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऐक्टिविटी जनवरी में करीब 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। यह बात एक मंथली सर्वे में कही गई है। सर्वे में कहा गया है कि डिमांड कंडीशंस बेहतर होने से नए बिजनेस ऑर्डर्स में तेज उछाल आया है। इसकी वजह से प्रॉडक्शन और हायरिंग एक्टिविटीज बढ़ी हैं। अगर मौजूदा स्थिति बरकरार रहती है तो आने वाले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार दिखने लगेगा। बता दें कि जुलाई-सितंबर तिमाही में विकास की रफ्तार छह साल में सबसे धीमी थी। मांग बढ़ने के कारण जनवरी के महीने में कारोबार, उत्पादन, निर्यात और रोजगार के मौके बढ़े हैं। इस दौरान बिजनस सेंटिमेंट में मजबूती आई है हालांकि इस दौरान इनपुट कॉस्ट और आउटपुट चार्ज में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनियों के पर्चेजिंग मैनेजर के बीच किए बीच किए जाने वाले मासिक सर्वेक्षण

आईएचएस मार्किट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स (मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई) जनवरी में 55.3 अंक रहा है। यह 2012 से 2020 की अवधि में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले दिसंबर में यह 52.7 अंक था। जबकि साल भर पहले जनवरी 2019 में यह आंकड़ा 53.9 अंक था। यह लगातार 30वां महीना है जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 अंक से ऊपर रहा है। पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार जबकि 50 अंक से नीचे रहना दबाव के रुख को दर्शाता है। IHS मार्केट की प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियेना डि लीमा ने बताया, 'जनवरी में भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में मजबूती लगातार बनी हुई है। पिछले 8 सालों में उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।' जनवरी में विनिर्माण पीएमआई के उच्च स्तर पर रहने की अहम वजह मांग में सुधार होना है। इसकी वजह से नए ऑर्डर मिलने, उत्पादन, निर्यात और विनिर्माण के लिए खरीदारी और रोजगार में बढ़त देखी गई है। साथ ही कारोबारी धारणा में भी सुधार हुआ है। डि लिमा ने कहा, 'जनवरी में देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। परिचालनात्मक परिस्थियों में जिस गति से सुधार देखा गया है, ऐसा पिछले 8 साल की अवधि में नहीं देखा गया।' सर्वेक्षण में कंपनियों ने माना कि नए ऑर्डर मिलने में जो मजबूती देखी गई है वह पिछले पांच साल की अवधि में नहीं देखी गई। इसकी प्रमुख वजह मांग का बढ़ना और ग्राहक की जरूरतों का सुधार होना है। कंपनियों की कुल बिक्री में विदेशी बाजारों से बढ़ी मांग की अहम भूमिका है। यह नवंबर 2018 के बाद निर्यात के नए ऑर्डरों में सबसे तेज बढ़त है। वहीं, रोजगार के स्तर पर जनवरी में रोजगार गतिविधियों में भी सुधार देखा गया है। क्षेत्र में रोजगार की दर पिछले साढ़े सात साल में सबसे तेज है। बाजार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जारी होने का भी इंतजार है। इसमें बाजार मांग को और बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4-6 फरवरी 2020 को होना है।

सोने-चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने-चांदी के कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक बुलियन मार्केट में बुधवार को 10 ग्राम सोना 220 रुपया टूटकर 40386 रुपये पर खुला। मंगलवार को यह 40606 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बता दें सराफा बाजार में सोने-चांदी के जेवर के रेट इससे अलग हो सकते हैं। गौरतलब है कि बुलियन सोना और चांदी है जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है और यह सिल्लियों या बार के रूप में होता है।

क्या है बुलियन मार्केट

सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं का व्यापार बुलियन मार्केट के जरिए ही होता है। सोने की खरीद दो तरह से की जाती है। आम लोग सर्राफा बाजार से सोने की खरीददारी करते हैं। वहीं कारोबारी लोग वायदा बाजार के जरिए सोने की खरीददारी करते हैं। बुलियन मार्केट वह जगह होती है जहां सोने-चांदी का व्यापार वायदा बाजार (फ्यूचर मार्केट) के जरिए होता है। वहीं दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार 4 फरवरी को 480 रुपये लुढ़ककर करीब एक सप्ताह के निचले स्तर 41,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। यह 200 रुपये की गिरावट में 47,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। यह सोने-चांदी का 29 जनवरी के बाद का निचला स्तर था।

पूरी रणनीति के साथ किया गया आयात शुल्क में वृद्धि का फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

जिस तरह से वित्त मंत्री ने आम बजट 2020-21 में एक साथ 76 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है उसको लेकर कई विशेषज्ञों ने आश्चर्य जताया है लेकिन वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों का कहना है कि एक एक आइटम पर सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला काफी सोच विचार कर हुआ है। उन उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है जिनके आयात पर काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही थी। साथ ही इन उत्पादों को भारत में बनाने की पूरी क्षमता है लेकिन सस्ते आयात की वजह से भारतीय इकाइयों को हानि हो रही थी। ऐसे में वाणिज्य मंत्रालय के विमर्श के बाद उन उत्पादों का चयन किया गया है जिनके आयात को हतोत्साहित करके भारत में उनके निर्माण को बढ़ावा मिले।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिन उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है वे तकरीबन सारे के सारे चीन से मंगाये जा रहे थे। इस तरह से सरकार का कदम चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को थामने में भी मदद करेगा।इसी उद्देश्य से आम बजट में फर्नीचर व कई तरह के इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरणों पर आयात शुल्क 10 फीसद से बढ़ा कर 20 फीसद किया है। मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ने से भारत में फर्नीचर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अभी यह 6 अरब डॉलर का हो गया है। लेकिन चीन की कंपनियां इस बाजार पर हावी हो रही थी।

पिछले वित्त वर्ष चीन से तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का फर्नीचर आयात किया गया। लेकिन बाजार के सूत्रों के मुताबिक फर्नीचर की कीमत तय करने का कोई अंतरराष्ट्रीय ठोस मानक नहीं होने की वजह से कंपनियां इसकी आड़ में कालाबाजारी भी कर रही थी। यह सब रुकेगा। साथ ही देश के कई शहरों में फर्नीचर कलस्टर बनाने की भी प्लानिंग है ताकि आयात प्रतिबंधित होने के बाद घरेलू मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। घरेलू मांग पूरा करने के साथ ही भारत की नजर वैश्विक फर्नीचर बाजार पर भी है जो 264 अरब डॉलर की है। विएतनाम जैसे देश भी 11 अरब डॉलर का फर्नीचर निर्यात करता है। भारत पिछले महीने ही वर्ल्ड फर्नीचर काउंसिल का सदस्य बना है ताकि वैश्विक बाजार का फायदा उठा सके।

बजट के जरिए फुटवियर, फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान, किचन सामग्री, क्ले से बने उत्पाद व सेरामिक से बने सारे घरेलू उपकरणों, टेबल, किचन, कार्यालय में सजावट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कांच के उपकरणों, तांबे, अल्यूमियिनम के बने सजावटी घरेलू उपकरणों पर भी सीमा शुल्क 10 फीसद से बढ़ा कर 20 फीसद कर दिया है। मोटे तौर पर भारत में इनके समेत कुछ दूसरे सजावटी उपकरणों का आयात 10 अरब डॉलर का सालाना है। इसका ज्यादातर हिस्सा चीन से ही आता है। जानकारों का कहना है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की वजह से चीन बहुत ही कम मार्जिन पर इनका निर्यात भारत को करता है। 10 फीसद की सीमा शुल्क बढ़ाने से भी इन उत्पादों को भारत भेजने की लागत बढ़ जाएगी। यह थोड़ा ही सही लेकिन चीन के साथ कारोबार घाटे को पाटने में मददगार साबित होगा। पिछले वित्त वर्ष भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 56 अरब डॉलर का रहा था।

भारत को पाम तेल निर्यात की अड़चन दूर होने के इंतजार में मलेशिया

नई दिल्ली। एजेंसी

मलेशिया को उम्मीद है कि भारत को पाम तेल बेचने की राह में आई अड़चन को वह जल्द ही दूर कर लेगा, क्योंकि मलेशियन पाम काउंसिल ने मंगलवार को एक मंत्री के हवाले से कहा है कि भारत द्वारा मलेशिया से पाम तेल की खरीद पर रोक अस्थाई है। भारत के घरेलू मसलों पर मलेशिया की टिप्पणी से दोनों देशों के बीच आई तल्खी के बाद भारत ने मलेशिया से पाम तेल आयात करना बंद कर दिया है, जिससे मलेशिया के तेल निर्यात पर काफी असर पड़ने की संभावना है। खाद्य तेल उद्योग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (?एसईए) के कार्यकारी निदेशक डॉ. बीवी मेहता ने के अनुसार भारत मलेशिया से पाम तेल का प्रमुख खरीददार है, जो सालाना 30-40 लाख टन पाम तेल मलेशिया से खरीदता रहा है, लेकिन इस समय भारत ने मलेशिया से पाम तेल खरीदना बंद कर दिया है। मलेशिया की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उसकी खरीददारी पर भी असर पड़ा है।

पाम तेल का मलेशिया की जीडीपी में 3.8 फीसदी हिस्सा

पाम तेल का मलेशिया की जीडीपी में 3.8 फीसदी और लगभग 77 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है। यह मलेशिया के

कृषि उत्पादों में सबसे अग्रणी उत्पाद है। मलेशियन पाम काउंसिल के मुताबिक, भारत की खरीददारी पर रोक अस्थाई है और दोनों देश मिलकर जल्द ही इसका समाधान कर लेंगे। यह बात मलेशिया के उद्योग मंत्री टेरेसा कोक के बयान का जिक्र करते हुए कही गई है। पिछले साल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने भारत विरोधी बयान दिया था। इसके बाद भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भी मलेशिया ने तल्ख टिप्पणी की थी।

भारत ने हाल ही में रिफाइंड तेलों के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला

डॉ. बीवी मेहता ने कहा कि भारत पाम तेल का आयात मलेशिया से कहीं ज्यादा इंडोनेशिया से करता है, इसलिए भारत को मलेशिया से पाम तेल आयात बंद होने से कोई परेशानी नहीं है। अगर भारत सरकार तेल आयात की अनुमति देती भी है तो भारत सिर्फ क्रूड पाम तेल का आयात करना चाहेगा, आरबीडी पाम तेल की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने मलेशिया और इंडोनेशिया से रिफाइंड पाम तेल आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया है और इसके आयात के लिए सरकार ने अभी तक किसी को लाइसेंस भी जारी नहीं किया है। वहीं, क्रूड पाम तेल की खरीददारी भी इस समय मलेशिया से नहीं हो रही है। जिस कारण मलेशिया की चिंता बढ़ गई है।

संन्यास के संकल्प का प्रतीक है गेरुआ वस्त्र

मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है गेरुआ वस्त्र। यह तो मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता का सूचक है। ये अपने आप में गंतव्य नहीं है, बल्कि उस ओर प्रस्थान की तैयारी है। जब आप किसी काम के लिए तैयार होंगे, तभी उसे पूरा कर पाने की संभावना बनेगी।

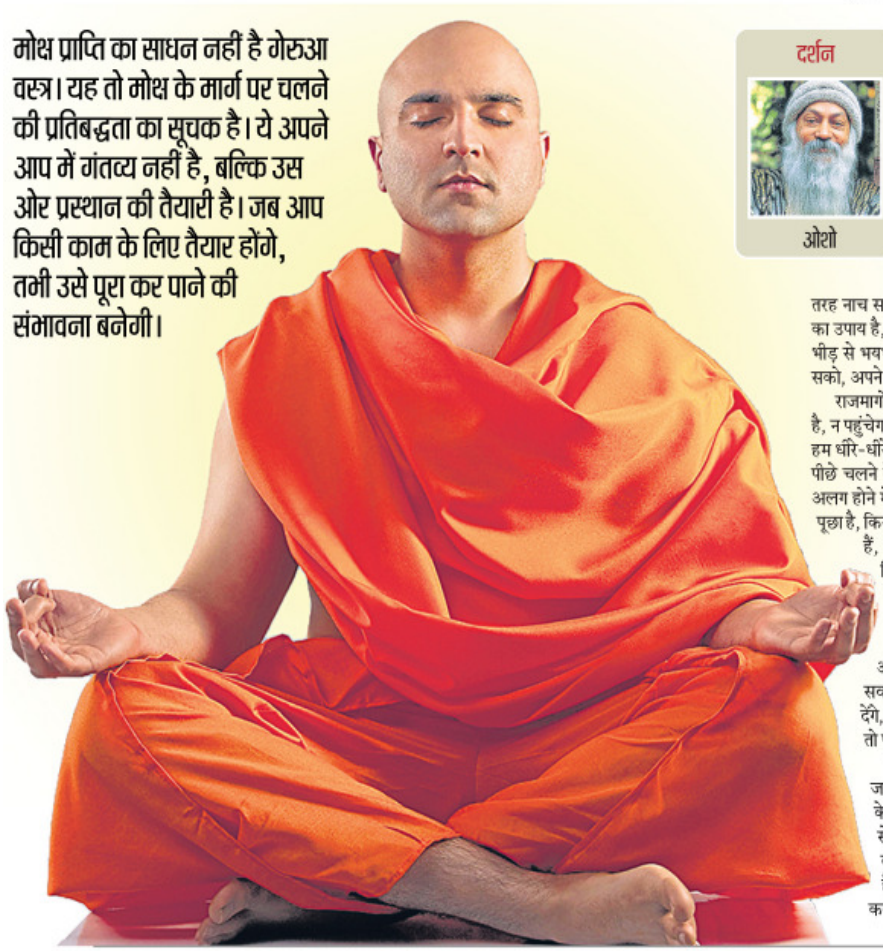

दर्शन

ओशो

अंतरतम में उतरना हो तो थोड़ा पागल होना जरूरी है। ये पागल होने के रास्ते हैं, और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी होशियारी को तोड़ने के रास्ते हैं, और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी समझदारी को पोंछने के रास्ते हैं, और कुछ भी नहीं। गेरुआ वस्त्र पहना दिया, बना दिया पागल! अब जहां जाओगे, वहीं हंसाई होगी। जहां जाओगे, लोग वहीं चैन से न खड़ा रहने देंगे। सब आंखें तुम पर होंगी। हर कोई तुमसे पूछेगा: 'क्या हो गया?' हर आंख तुम्हें कहती मालूम पड़ेगी, 'कुछ गड़बड़ हो गई। तो तुम भी इस उपद्रव में पड़ गए? सम्मोहित हो गए?'

गेरुआ वस्त्रों का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। कोई गेरुआ वस्त्रों से तुम मोक्ष को न पा जाओगे। गेरुआ वस्त्रों का मूल्य इतना ही है कि तुमने एक घोषणा की, कि तुम पागल होने को तैयार हो। तो फिर आगे और यात्रा हो सकती है। यहीं तुम डर गए तो आगे क्या यात्रा होगी? आज तुम्हें गेरुआ वस्त्र पहना दिए, कल एकतारा भी पकड़ा देंगे। उंगली हाथ में आ गई तो पहुंचा भी पकड़ लेंगे। यह तो पहचान के लिए है कि आदमी हिम्मतवर है या नहीं। हिम्मतवर है तो धीरे-धीरे और भी हिम्मत बढ़ा देंगे। आशा तो यही है कि कभी तुम सड़कों पर मीरा और चैतन्य की तरह नाच सको। ये गेरुआ वस्त्र तुम्हें भीड़ से अलग करने का उपाय है, तुम्हें व्यक्तित्व देने की व्यवस्था है; ताकि तुम भीड़ से भयभीत होना छोड़ दो; ताकि तुम अपना स्वर उठा सको, अपने पैर उठा सको, पगडंडी को चुन सको।

राजमार्गों से कोई कभी परमात्मा तक न पहुंचा है, न पहुंचेगा; पगडंडियों से पहुंचता है। और हम धीरे-धीरे इतने आदी हो गए हैं भीड़ के पीछे चलने के, कि जरा-सा भी भीड़ से अलग होने में डर लगता है। जिन मित्र ने पूछा है, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, बुद्धिमान हैं, सुशिक्षित हैं... फिर विश्वविद्यालय में गेरुआ वस्त्र पहन कर जाएंगे, तो अड़चन मैं समझता हूं।

> गेरुआ वस्त्रों का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। गेरुआ वस्त्रों से तुम मोक्ष न पा जाओगे। गेरुआ वस्त्रों का मूल्य इतना ही है कि तुमने एक घोषणा की, कि तुम पागल होने को तैयार हो। तो फिर आगे और यात्रा हो सकती है।

प्रश्न पूछा है तो जानता हूं कि मन में आकांक्षा भी जगी है, नहीं तो पूछते क्यों। अब सवाल है... हिम्मत से चुनेंगे, कि फिर हिम्मत छोड़ देंगे, साहस खो देंगे? कठिन तो होगा। कहना हो, यही तो पूरी व्यवस्था है।

पूछा है कि माला वस्त्रों के ऊपर ही पहननी क्यों जरूरी है। इच्छा पहनने की साफ है, मगर कपड़ों के भीतर पहनने की इच्छा है। नहीं, भीतर पहनने से न चलेगा; वह तो ना पहनने के बराबर हो गया। वह बाहर पहनाने के लिए कारण है। कारण यही है कि तुम्हें किसी तरह भी भीड़ के भय से मुक्त करवाना है... किसी भी तरह। किसी भी भांति तुम्हारे जीवन से यह चिंता चली जाए कि दूसरे क्या कहते हैं, तो ही आगे कदम उठ सकते हैं। अगर परमात्मा का होना है तो समाज से थोड़ा दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज तो बिल्कुल ही परमात्मा का नहीं है। समाज के ढांचे से थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा।

न तो माला का कोई मूल्य है, न गेरुआ वस्त्रों का कोई मूल्य है; अपने आप में कोई मूल्य नहीं है... मूल्य किसी और कारण से है। अगर यह सारा मुल्क ही गेरुआ वस्त्र पहनता हो तो मैं तुम्हें गेरुआ वस्त्र न पहनाऊंगा; तो मैं कुछ और चुन लूंगा: काले वस्त्र, नीले वस्त्र। अगर यह सारा मुल्क ही माला पहनता हो तो मैं तुम्हें माला न पहनाऊंगा; कुछ और उपाय चुन लेंगे। बहुत उपाय लोगों ने चुने। बौद्ध भिक्षुओं ने केश त्याग किया, उपाय है। अलग हो गए। महावीर दिगंबर हो गए।

थोड़ा सोचो, जिन लोगों ने इन लोगों का अनुसरण करने की सोची होगी, जरा उनके साहस की खबर करो। जरा विचारो। उस साहस में ही सत्य ने उनके द्वार पर आकर दस्तक दे दी होगी। बुद्ध ने राजपुत्रों को, संपत्तिशालियों को धनत्याग कराया, भिक्षापात्र हाथ में दे दिए। जिनके पास कोई कमी न थी, उन्हें भिखारी बनाने का क्या प्रयोजन रहा होगा? अगर भिक्षा से परमात्मा मिलता है तो कई को कभी का मिल गया होता। नहीं, इसका सवाल न था... दरअसल उन्हें उतार कर लाना था वहां, जहां वे निपट पागल सिद्ध हो जाएं। उन्हें तर्क की दुनिया से बाहर खींच लाना था। उन्हें हिसाब-किताब की दुनिया के बाहर खींच लाना था। जो साहसी थे, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जो कायर थे, उन्होंने अपने भीतर तर्क खोज लिए। उन्होंने कहा, क्या होगा सिर घुटाने से? क्या होगा दिगंबर होने से? क्या होगा गेरुआ वस्त्र पहनने से?

यह असली सवाल नहीं है। असली सवाल यह है, तुममें हिम्मत है? पूछो यह बात कि क्या होगा हिम्मत से। हिम्मत से सब कुछ होता है। साहस के अतिरिक्त और कोई उपाय आदमी के पास नहीं है। दुस्साहस चाहिए! लोग हंसेंगे। लोग मखौल उड़ाएंगे। और तुम निश्चिंत अपने मार्ग पर चलते जाना। तुम उनकी हंसी की फिक्र न करना। तुम उनकी हंसी से डांवाडोल न होना। तुम उनकी हंसी से व्यथित मत होना। और तुम पाओगे, उनकी हंसी भी सहारा हो गई; और उनकी हंसी ने भी तुम्हारे ध्यान को व्यवस्थित किया; और उनकी हंसी ने भी तुम्हारे भीतर से क्रोध को विसर्जित किया; और उनकी हंसी ने भी तुम्हारे जीवन में करुणा का प्रवेश किया। यह सब समाज के दायरे से मुक्त करने की व्यवस्था है। जिसको मुक्त होना हो और जिसे थोड़ी हिम्मत हो अपने भीतर, भरोसा हो थोड़ा अपने पर; अगर तुम बिल्कुल ही बिक नहीं गए हो समाज के हाथों; और अगर तुमने अपनी सारी आत्मा गिरवी नहीं रख दी है; तो चुनौती स्वीकार कर लो।

सत्य कमजोरों के लिए नहीं है, साहसियों के लिए है। गेरुआ का सत्य उस मार्ग पर जाने के लिए है, जहां आपको साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है, जब तक परमात्मा ना मिल जाएं।

(सौजन्यः ओशोधारा नानक धाम, मुरथल, सोनीपत)

जया एकादशी (5 फरवरी) पर विशेष

सभी कामनाओं की पूर्ति का व्रत

स्नान-दान और पुण्य प्रभाव के माह माघ मास की शुक्लपक्ष एकादशी को जया एकादशी कहा गया है। इसी दिन भक्त पुण्डरीक का उत्सव पंढरपुर (महाराष्ट्र) में मनाया जाता है। जया एकादशी के पुण्य के कारण मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर जीवन के हरेक क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त करता है और मोक्ष का

अधिकारी हो जाता है। भागवत पुराण में आया है कि जो मनुष्य समस्त भौतिक तथा सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए।

सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली इस एकादशी की कथा का वर्णन 'पद्मपुराण' सहित कई प्राचीन आख्यानों में है। कथा है- एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती, माल्यवान को देख कर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा- तुम दोनों ने न सिर्फ यहां की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री-पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो।

इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वतादि क्षेत्र में अपना जीवन दुखपूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्लपक्ष एकादशी तिथि आ गयी। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गयी, पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पवर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, 'जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है।'

डॉ. राकेश कुमार सिन्हा 'रवि'

आस्था स्थली: मां पूर्णागिरि मंदिर, टनकपुर, उत्तराखंड

हिमालय में बसा मां का सिद्धपीठ

मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत जिले की तहसील टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहां पर माता का वक्ष गिरा था।

टनकपुर शहर से पूर्णागिरी मंदिर के आधार तल की दूरी 21 किलोमीटर है। मंदिर के आधार तल से श्रद्धालुओं को तीन किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। सिर्फ पैदल चलने में सक्षम लोग ही मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पार्किंग से लेकर अगले दो किलोमीटर तक मंदिर के पैदल यात्रा मार्ग में दोनों तरफ दुकानें, खाने-पीने के रेस्टोरेंट और रहने के लिए छोटी-छोटी धर्मशालाएं बनी हैं।

पदयात्रा की शुरुआत करते ही सबसे पहले भैरव मंदिर आता है। काफी श्रद्धालु भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा होगा कि आप छाता, टॉर्च, रेनकोट आदि लेकर माता के दरबार तक पदयात्रा करें। तकरीबन एक किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर आता है, उसका नाम है झूठे का मंदिर। कहा जाता है कि एक श्रद्धालु ने माता का मंदिर यहां निर्मित कराया, पर उसने सोने की जगह नकली सुनहले रंगों का इस्तेमाल किया। लोग इस मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं, पर यह झूठे के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है।

तकरीबन दो किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में मां काली का मंदिर आता है। वापसी में काफी श्रद्धालु इस मंदिर में भी आस्था से पूजन करते हैं। तकरीबन तीन किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हुए आप मां पूर्णागिरी के दरबार में पहुंच जाते हैं। होली के बाद आने वाली नवरात्रि से माता पूर्णागिरी का मेला शुरू हो जाता है। यह मेला तीन महीने तक चलता है। यानी अप्रैल, मई और जून महीने में। तब माता पूर्णागिरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।

कैसे पहुंचें: उत्तर प्रदेश के बरेली से टनकपुर रेल या बस से जा सकते हैं। टनकपुर इस मार्ग का आखिरी रेलवे स्टेशन है। टनकपुर शहर से पूर्णागिरी मंदिर तक के लिए जीप मिलती है।

माधवी रंजना

Auto Expo 2020

Maruti Suzuki Futuro-e कॉन्सेप्ट कार से उठा पर्दा

नई दिल्ली। एजेंसी

Auto Expo 2020 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ Maruti Suzuki ves Futuro-e concept से पर्दा उठा दिया। इस कार से मारुति ने भविष्य में उसकी आने वाली कारों की स्टाइलिंग की एक झलक दिखाने की कोशिश की है। Futuro-e कॉन्सेप्ट कार के साथ मारुति ने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी एंट्री भी बता दी है। फ्यूचरो-ई को मारुति सुजुकी की डिजाइन टीम ने डिजाइन किया है। एसयूवी-कूप शेप वाली इस कॉन्सेप्ट कार से मारुति ने टिपिकल मिडसाइज एसयूवी से कुछ अलग करने की क्षमता को दिखाया है। रियर विंडस्क्रीन की रेक Futuro-e को स्पोर्टी लुक देता है। इसके अलावा कार पर दिया गया शार्प लुक वाला ग्लासहाउस और मोटा सी-पिलर इसके लुक को शानदार बनाते हैं। सामने से यह कॉन्सेप्ट कार काफी बोल्ड दिखती है। पीछे लंबी और पतली टेललाइट काफी यूनीक हैं।

इंटीरियर

मारुति फ्यूचरो-ई का इंटीरियर काफी मॉडर्न है। डैशबोर्ड पर बड़ी स्क्रीन दी गई है। फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग के आगे डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और इंटीरियर के लिए कंट्रोल्स हैं। इस कूप-स्टाइल एसयूवी में ऐम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। कॉन्सेप्ट कार को 4-सीटर ऑप्शन में पेश किया गया है।

भविष्य के लिए तैयार

इस कॉन्सेप्ट एसयूवी के नाम में 'E' जुड़ा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट है। मारुति का दावा है कि एसयूवी-कूप कॉन्सेप्ट हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ भविष्य के लिए तैयार है। हालांकि, इस कॉन्सेप्ट एसयूवी के प्रॉडक्शन वर्जन को पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारा जाएगा। साथ ही अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को देखते हुए कंपनी इसमें डीजल इंजन भी दे सकती है।

इनसे होगा मुकाबला

मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में यह जानकारी नहीं दी है कि फ्यूचरो-ई कॉन्सेप्ट का प्रॉडक्शन कब शुरू होगा। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचरो-ई का प्रॉडक्शन वर्जन इस कॉन्सेप्ट से कितना मिलता-जुलता होगा। हालांकि, इसकी शार्प स्टाइलिंग मारुति को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने में मदद कर सकती है। मार्केट में इस कॉन्सेप्ट एसयूवी के प्रॉडक्शन वर्जन की टक्कर ह्यूंदै क्रेटा और किआ सेल्टॉस जैसी एसयूवी से होगी।

ऑटो एक्सपो में टाटा की इन शानदार कारों का जलवा

नई दिल्ली। एजेंसी

Auto Expo 2020 में Tata Motors का पविलियन लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। टाटा के पविलियन में कई शानदार कारें हैं, जिनमें कुछ मॉडल्स बेहद खास हैं। इनमें से एक कार टाटा की बहुप्रतीक्षित 7-सीटर एसयूवी Gravitas है। इसके अलावा मिनी एसयूवी Tata HBX का नियर प्रॉडक्शन मॉडल और Tata Sierra इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए आपको ऑटो एक्सपो में आई टाटा की खास कारों के बारे में बताते हैं।

Tata Gravitas

टाटा मोटर्स ने साल 2019 में हुए जिनेवा मोटर शो में इसे टाटा बजार्ड नाम से पेश किया था। मार्केट में यह कार टाटा ग्रैविटस नाम से आएगी। यह हैरियर एसयूवी का 7-सीटर वर्जन है। पीछे तीसरी लाइन की सीट देने के लिए इसकी लंबाई को हैरियर के मुकाबले थोड़ा बढ़ाया गया है। हैरियर के मुकाबले इसकी रूफ पीछे की तरफ थोड़ी ऊंची है और साइड विंडो को भी बड़ा किया गया है। इसमें भी हैरियर वाला बीएस6 2.0-लीटर इंजन मिलेगा, जो 170प्ज का पावर और 350Nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है।

Tata Sierra

टाटा मोटर्स की 90 के दशक में आने वाली सिएरा एसयूवी ने एक बार फिर वापसी की है। ऑटो एक्सपो में टाटा ने सिएरा नाम से इलेक्ट्रिक एसयूवी का कॉन्सेप्ट पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्ट्रॉज वाले ALFA प्लैटफॉर्म पर आधारित है। यह तीन दरवाजे वाली कार है। इसमें दाहिने तरफ रियर डोर नहीं दिया गया है। इसके अलावा इसका इंटीरियर भी यूनीक है। सिएरा में पीछे की तरफ रियर बेंच के साथ लाउंज जैसा सीटिंग एरिया है। इसके पावरट्रेन के बारे में अभी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

Tata HBX

यह टाटा मोटर्स की मिनी एसयूवी है। इसे बाजार में नेक्सॉन के नीचे की रेंज में उतारा जाएगा। ऑटो एक्सपो में इसका नियर प्रॉडक्शन मॉडल (काफी हद तक फाइनल मॉडल) पेश किया गया है। इसमें टाटा हैरियर की स्टाइल में डीआरएल दिए गए हैं। इसमें टाटा की लेटेस्ट IMPACT 2.0 डिजाइन लैंग्वेज का यूज हुआ है।

Tata Harrier BS6

ऑटो एक्सपो में टाटा ने हैरियर एसयूवी का बीएस6 मॉडल लॉन्च कर दिया। बीएस6 में अपग्रेड होने के साथ ही इसकी कीमत भी 25-30 हजार रुपये तक बढ़ गई है। टाटा हैरियर की शुरुआती कीमत अब 13.69 लाख रुपये है। बीएस6 के साथ ही कंपनी ने हैरियर में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी शामिल कर दिया है। टाटा हैरियर का बीएस6 इंजन 170प्ज का पावर जेनरेट करता है, जबकि बीएस4 वर्जन में यह 140प्ज का पावर जेनरेट करता था।

बंदरगाहों पर सड़ रहा है आयातित प्याज 22-23 रुपये किलो पर बेचने की तैयारी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार बंदरगाहों पर सड़ रहे आयातित प्याज को काफी सस्ती दर पर यानी 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेच सकती है। यह भाव प्याज के मौजूदा बाजार भाव की तुलना में करीब 60 प्रतिशत कम है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार अभी राज्य सरकारों को 58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयातित प्याज मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार परिवहन का खर्च भी वहन कर रही है।

सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए नवंबर, 2019 में एमएमटीसी के जरिए 1.2 लाख टन प्याज का आयात करने का निर्णय लिया था। एमएमटीसी विदेशी बाजारों से 14 हजार टन प्याज का आयात कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि आयातित

प्याज की बड़ी खेप बंदरगाहों विशेषकर महाराष्ट्र में पड़ी हुई है। नई फसल के बाजार में पहुंचने से खुदरा कीमतें नरम पड़ने लगी हैं। ऐसे में कई राज्य उच्च दर पर आयातित प्याज खरीदने को तैयार नहीं हैं।

सूत्रों ने कहा कि आयातित प्याज का स्वाद भी घरेलू प्याज की तुलना में अलग है। इसके कारण कई राज्यों ने आयातित प्याज के ठेके रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि आयातित प्याज की नरम मांग को देखते हुए एमएमटीसी ने अभी तक महज 14 हजार टन प्याज की ही खरीद की है, जबकि उसने 40 हजार टन प्याज आयात करने के ठेके दिए हैं। अभी तक आयातित प्याज की बड़ी खेप भी बंदरगाहों पर पड़ी है। नेफेड, मदर डेयरी और इच्छुक राज्य सरकारें मंडियों में वितरण के लिए 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयातित प्याज खरीद सकती हैं।

अप्रैल-दिसंबर में देश का कोयला आयात आठ प्रतिशत बढ़कर 18.58 करोड़ टन

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर की अवधि में 7.6 प्रतिशत बढ़कर 18.58 करोड़ टन पर पहुंच गया। एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में कोयला आयात 13.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.05 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 1.81 करोड़ टन रहा था। दिसंबर में नॉन कोकिंग कोयले आयात बढ़कर 1.42 करोड़ टन रहा। यह दिसंबर, 2018 में 1.25 करोड़ टन रहा था। इसी तरह कोकिंग कोयले का आयात 44.7 लाख टन रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 37.6 लाख टन रहा था। एमजंक्शन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय वर्मा ने कहा, "दिसंबर में आयात गतिविधियां कुछ बढ़ीं। इसकी वजह इस्पात कीमतों में सुधार और सीमेंट और स्पॉन्ज आयरन क्षेत्रों से सतत मांग बने रहना है।" भारत ने 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 23.52 करोड़ टन कोयले का आयात किया था।

नई आयकर व्यवस्था में भी वीआरएस में मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की राशि होगी कर मुक्त

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी।वित्त मंत्री ने शनिवार को संसद में पेश 2020-21 के बजट में व्यक्तिगत आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था में पांच लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया। पुरानी कर व्यवस्था में 120 के करीब छूट और रियायतें दी गईं थी इनमें से 70 को हटाया गया है।

नई कर व्यवस्था के तहत जो कर छूट और रियायतें उपलब्ध होंगी वे इस प्रकार हैं

■कृषि से होने वाली आय ■अविभाजित हिंदू परिवार के किसी सदस्य को परिवार की संपत्ति से मिलने वाला धन ■कंपनी के भागीदार को मिलने वाला लाभ का हिस्सा ■प्रवासी भारतीयों को कुछ प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों तथा प्रावासी (बाह्य) खाते में रखे धन पर मिलने वाला ब्याज ■विदेशी राजनयिकों, दलों तथा प्रशिक्षुओं को होने वाली आय ■विदेश में सेवा के बदले किसी भारतीय नागरिक को भारत सरकार से मिलने वाली राशि ■मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रैच्यूटी (सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई सीमा नहीं, अन्य के लिये 20 लाख रुपये तक) ■ सेवानिवृत्ति के समय बची छुट्टियों के बदले मिलने वाली नकदी (सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई सीमा नहीं, अन्य के लिये तीन लाख रुपये तक) ■भोपाल गैस त्रासदी के भुक्तभोगियों को मिलने वाला मुआवजा ■किसी आपदा की स्थिति में सरकार से मिलने वाली सहायता राशि ■वीआरएस के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि होगी कर मुक्त ■जीवन बीमा पॉलिसी से बोनस समेत मिलनी वाली राशि (कुछ शर्तों के साथ) ■मृत्यु पर बीमा से मिलने वाली राशि (बिना शर्तों के) ■जीपीएफ या पीपीएफ से मिलने वाला ब्याज ■सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि ■एनपीएस को बंद करने पर मिलने वाला भुगतान व आंशिक निकासी ■पेंशन मद में मिलने वाला भुगतान (कुछ शर्तों के साथ) ■छात्रवृत्ति की राशि ■सरकार या सरकारी संस्थान से किसी सम्मान के साथ मिलने वाली राशि ■ शौर्य सम्मान के तहत मिलने वाली पेंशन ■नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अथवा नॉर्थ चाचर हिल्स, मिकिर हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स अथवा लद्दाख के जिले के निवासियों को लाभांश के तौर पर या प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय ■ सिक्किम के निवासियों को सरकार से अथवा लाभांश के तौर पर या प्रतिभूतियों के ब्याज से होने वाली आय

हर साल मिलेगी इनकम टैक्स का नया या पुराना सिस्टम चुनने की छूट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन पी सी मोदी ने कहा कि टैक्सपेयर्स के पास यह मौका हर साल रहेगा कि वे कम रेट और बिना एग्जम्पशंस वाली इनकम टैक्स की नई व्यवस्था और पुराने सिस्टम में से किसी एक का चयन कर सकें।

उन्होंने कहा कि एक बार किसी स्कीम का चयन कर लेने के बाद अगले साल वापस लौटने का विकल्प भी होगा। हालांकि बिजनस चलाने वालों को एक से दूसरी स्कीम में शिफ्ट होकर वापस आने का विकल्प नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, 'यह साफ समझ लें कि यह ऑप्शनल स्कीम है। आपके सामने नई स्कीम में जाने की कोई मजबूरी नहीं है।' उन्होंने कहा, 'अगर आपको नई स्कीम बेहतर लगे तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप पुराने सिस्टम में अच्छा महसूस कर रहे हों तो वहीं बने रहें।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली फरवरी को पेश किए गए आम बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब्स का प्रस्ताव दिया था। मोदी ने कहा, 'एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि एक से दूसरी स्कीम में आने-जाने का विकल्प आपको सालाना आधार पर उपलब्ध है।' उन्होंने कहा, 'अगर किसी को लगे कि किसी खास वर्ष में कोई डिडक्शन लेने के लिए पुराना सेटअप बेहतर है तो वह उसे चुने। अगर उसे लगे कि नए सिस्टम में रेट बेहतर है तो वह इसे चुन सकता है। प्रतिबंध केवल उन लोगों के मामले में है, जिनके पास बिजनस है।'

सीतारमण की बात दोहराते हुए मोदी ने कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बनाने के लिए डिडक्शन और एग्जम्पशन को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। सरकार रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए प्री-फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म मुहैया कराने की योजना भी बना रही है। टैक्स के दायरे में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का ज्यादा हिस्सा आने से टैक्स रेट्स को घटाने का चांस बनेगा। मोदी ने कहा, 'अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का इतना ही हिस्सा (संभावित करदाता) टैक्स फ्रेमवर्क के दायरे में होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि टैक्स रेट और घटाने की जमीन इससे बनेगी। बेस जितना बड़ा होगा, इनकम टैक्स रेट्स में कमी करने की उतनी ही गुंजाइश होगी।' सरकार संभावित टैक्सपेयर्स को यह समझाने का प्रयास करेगी कि उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। सीतारमण ने कहा था कि CBDT एक टैक्सपेयर चार्टर अपनाएगा ताकि हैरासमेंट खत्म किया जा सके। बजट के अनुसार, CBDT विवाद से विश्वास स्कीम के जरिए टैक्स से जुड़े मुकदमे घटाने की दिशा में काम कर रहा है।

बिना पेनाल्टी भरे 31 मार्च 2020 तक चुका सकते हैं आयकर

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने आयकर के पुराने विवादों को बिना पेनाल्टी खत्म करने का मौका दिया है। 31 मार्च 2020 तक कोई भी डिफाल्टर बिना पेनाल्टी आयकर चुका कर विवाद खत्म कर सकता है। यानी 31 मार्च 2020 के बाद लाभ उठाने वाले को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। योजना केवल 30 जून 2020 तक खुली। केंद्र सरकार की इस योजना से अकेले उत्तराखंड में ही 20 हजार के करीब ऐसे करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें पुराने आयकर के मामलों में नोटिस या पेनाल्टी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बड़ी संख्या में आयकर के केस अपील और न्यायालयों में भी चल रहे हैं। ऐसे सभी मामलों को अब आयकर जमा कर खत्म किया जा सकता है।

जल्दी जारी होगा नोटिफिकेशन

दरअसल सरकार पिछले साल केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क के पुराने मामलों को खत्म करने के लिए सबका विश्वास नाम की योजना लेकर आई थी, जिसके तहत पुराने टैक्स को बिना पेनाल्टी जमा करने की छूट दी गई थी। इस योजना को देश भर में कारोबारियों ने हाथों हाथ लिया। बड़ी संख्या में टैक्स के पुराने विवाद खत्म हुए और सरकार को राजस्व भी मिला।

आयकर चुकाकर पुराने विवाद खत्म करें

इसे देखते हुए अब आयकर डिफाल्टरों के लिए भी सबका विश्वास योजना लाई गई है। योजना के तहत भी आयकर चुकाकर पुराने विवाद खत्म किए जा सकते हैं। 31 मार्च 2020 इसकी अंतिम तिथि तय की गई है। योजना को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द नोटिफिकेशन करेगा जिसके बाद इसके सभी पहलू सामने आएंगे। हो सकता है कि सरकार पुराना आयकर जमा करने पर छूट भी दे। हालांकि अभी यह तय नहीं है। टैक्स अधीक्षक तापस चक्रवर्ती ने बताया बजट में आयकर डिफाल्टरों के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है।

31 दिसंबर तक 1.33 लाख से ज्यादा करदाताओं के आवेदन

मंत्रालय के अनुसार विभिन्न अर्धन्यायिक मंचों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और न्यायिक मंचों के तहत सेवाकर और उत्पाद शुल्क के कुल मिलाकर 3.6 लाख करोड़ रुपये की देनदारी वाले 1.83 लाख मामले लंबित हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना का लाभ उठाने के पात्र इन 1.84 लाख करदाताओं में से 31 दिसंबर 2019 की सुबह तक 1,33,661 करदाताओं ने आवेदन जमा कराए हैं।

69,550 करोड़ रु का टैक्स बकाया

आवेदन करने वाले इन करदाताओं पर 69,550 करोड़ रुपये का कर बकाया है। योजना के तहत राहत पाने के बाद इन्हें 30,627 करोड़ रुपये का कर भुगतान करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि सबका विश्वास योजना को करदाताओं ने अब तक की सबसे फायदे वाली योजना के तौर पर माना है। सरकार ने अब तक ऐसी जितनी भी योजनाओं की घोषणा की, उनमें यह सबसे ज्यादा पसंद की गई।

कारपोरेट टैक्स चोरी अब संगीन अपराध नहीं

टैक्स अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कारपोरेट टैक्स चोरी को संगीन अपराध की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया है। कारपोरेट टैक्स न देना अभी तक क्रिमिनल ऑफेंस था जिसे अब सरल किया जा रहा है।

जनवरी में हरित प्रमाणपत्रों की बिक्री 29 प्रतिशत घटकर 5.7 लाख इकाई

नयी दिल्ली। एजेंसी

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की बिक्री जनवरी महीने में 29 प्रतिशत घटकर 5.7 लाख इकाई पर आ गई। पिछले साल समान महीने में यह आंकड़ा 8.05 लाख इकाई का रहा था। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) में जनवरी में 3.63 लाख अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों का कारोबार हुआ। पिछले साल समान महीने में आईईएक्स पर 6.44 लाख हरित प्रमाणपत्र बिके थे। इसी तरह पावर एक्सचेंज आफ इंडिया (पीएक्सआईएल) पर आरईसी की बिक्री 2.07 लाख इकाइयों की रही। पिछले साल समान महीने में यह आंकड़ा1.61 लाख इकाई रहा था।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।